फ़िलहाल नरेन्द्र मोदी का कोई विकल्प नहीं

-मनोज कुमार झा

नरेन्द्र मोदी के सत्ता में आने से पहले ही से संभावना जताई जा रही थी कि इनकी सरकार पूरी मनमानी करेगी। ये बात पूरी तरह सच साबित हुई। आठ महीने पुरानी नरेन्द्र मोदी सरकार ने अब तक इस नकली जनतंत्र की सभी मर्यादाओं को भंग करने के सिवा और कुछ भी नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी की यह पहली पूर्ण बहुमत वाली सरकार है। वास्तव में यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ही सरकार है, जिसका बहुत पहले से ही यह सपना था कि येन-केन-प्रकारेन देश की सत्ता पर काबिज़ हो सके और विकल्पहीनता के शून्य और कांग्रेस एवं अन्य दलों की कमजोरी ने उसे यह सुनहरा मौका दे दिया। अब संघ के 'अच्छे दिन' हैं, वहीं आम जनता के ऐसे बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है, जिसके बारे में शायद उसने पहले कभी सोचा तक न हो। नरेंद्र मोदी की सरकार संघ चला रहा है और अब जल, जंगल और ज़मीन पर कब्ज़ा करने का कांग्रेस का जो अभियान पहले पूरा नहीं हो सका था, उम्मीद है कि संघ के शासन में पूरा हो जाएगा। नरेन्द्र मोदी अध्यादेशों के माध्यम से शासन कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने सत्तानशीं होते ही कर दी थी।

मोदी शासन व्यवस्था के ढांचे में मूलभूत बदलाव करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। संघ का तो एजेंडा ही था कि भारतीय संविधान में मूलभूत बदलाव किए जाएं। मोदी दवे पांव ही सही, उसी एजेंडे को लागू कर रहे हैं। यह देश और जनता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, पर नरेन्द्र मोदी का कोई विकल्प है भी नहीं।

यह अलग बात है कि जम्मू-कश्मीर चुनाव में उनका और उनके सहयोगी 'दंगा शिरोमणि' अमित शाह का मिशन पूरा नहीं हो पाया, पर जोड़तोड़ कर सरकार बनाने की पूरी कोशिश है और यह तय है कि वहां जो भी सरकार बनी, उस पर संघ का अच्छा-खासा प्रभाव रहेगा। संघ का एकमात्र लक्ष्य है सत्ता पर काबिज़ होना। किसी तरह की नैतिकता उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। यही कारण है कि चुनाव प्रचार के दौरान जिस पीडीपी की नरेन्द्र मोदी ने खिल्ली उड़ाई थी, उसी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं।

बहरहाल, योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग बनाना और उसका प्रमुख एक ऐसे शख्स को बनाना जो खुलेपन की अर्थव्यवस्था का पैरोकार है, साफ़ कर देता है कि नरेन्द्र मोदी के इरादे क्या है। 'मैं देश नहीं बिकने दूंगा' की घोषणा चुनाव प्रचार के दौरान करने वाले नरेन्द्र मोदी देश बेचने पर आमादा दिखते हैं। नया भूमि अधिग्रहण क़ानून ज़मीन पर से किसानों के हक़ को पूरी तरह खत्म करने वाला है। अब ज़मीन छीनी जाएगी। रही बात आत्महत्या की, तो अब ये कोई अपराध नहीं रहा। मोदी जी ने जीवन से निराश हो चुके लोग़ों के प्रति रहमदिली दिखाई है। जो मरना चाहता है, उसे इसकी पूरी छूट है।

महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान नरेन्द्र मोदी ने पहली बार आत्महत्या करने वाले किसानों का मुद्दा उठाया था और इसके लिए संभवत: तत्कालीन सरकारों को दोषी ठहराया था, पर उन्हें वही बात याद रहती है जिनका चुनावी लाभ वो ले सकें। महाराष्ट्र और देश के अन्य हिस्सों में लाखों किसानों ने आत्महत्या की है और अभी भी कर रहे है। उस दौरान भाजपा भी सत्ता में थी। पर कभी भी भाजपा सरकार ने इस मुद्दे पर संवेदनशीलता नहीं दिखाई। अब तो किसानों के ज़्यादा ही दुर्दिन आ रहे हैं, क्योंकि सरकार ज़मीन छीनेगी। किसानों की ज़मीन छीनी जाएगी, जंगलों पहाड़ों पर कब्ज़ा किया जाएगा, तब जाकर नरेन्द्र मोदी अपने देशी-विदेशी थैलीशाह आकाओं की पूरी सेवा कर पाएंगे, जिनके वो चौकीदार हैं।

इस बीच संघ परिवार के संगठन पूरे देश में धार्मिक उन्माद-उन्माद का माहौल बनाने में लगे हुए हैं। बड़े पैमाने पर साम्प्रदायिक घृणा फैलाई जा रही है। धर्मांतरण और घरवापसी का मुद्दा गरम है। मोदी के मंत्रियों का अपने जुबान पर कोई काबू नहीं है और विश्व हिन्दू परिषद् एवं अन्य संगठन कुछ इस हिसाब से काम कर रहे हैं, मानो 'सैंया भये कोतवाल तो अब डर काहे का।' संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भारत को अपने स्तर पर हिंदूराष्ट्र घोषित कर दिया है। धर्मांतरण एवं घरवापसी जैसे साम्प्रदायिक अभियानों पर नरेन्द्र मोदी मुंह खोलना जरूरी नहीं समझते। जहां तक अमित शाह का सवाल है, वो धर्मांतरण को उचित ठहराते हैं। हाल के दिनों में संघ के नेताओं के ज़हरबुझे बयान खूब सामने आए हैं। ये आते रहेंगे। पैसे देकर ग़रीबों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। कई जगहों पर दंगे फैलाने की सुनियोजित साजिश सामने आई है। दंगे अभी और फैलेंगे, क्योंकि मोदी और उनके सिपहसालार अमित शाह को भलीभांति मालूम है कि यही वो औज़ार है, जो कारगर होगा। नरेन्द्र मोदी के देश की सत्ता पर काबिज़ होने में साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण

महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान नरेन्द्र मोदी ने पहली बार आत्महत्या करने वाले किसानों का मुद्दा उठाया था और इसके लिए संभवत: तत्कालीन सरकारों को दोषी ठहराया था, पर उन्हें वही बात याद रहती है जिनका चुनावी लाभ वो ले सकें। महाराष्ट्र और देश के अन्य हिस्सों में लाखों किसानों ने आत्महत्या की है और अभी भी कर रहे है। उस दौरान भाजपा भी सत्ता में थी। पर कभी भी भाजपा सरकार ने इस मुद्दे पर संवेदनशीलता नहीं दिखाई। अब तो किसानों के ज़्यादा ही दुर्दिन आ रहे हैं, क्योंकि सरकार ज़मीन छीनेगी। किसानों की ज़मीन छीनी जाएगी, जंगलों पहाड़ों पर कब्ज़ा किया जाएगा, तब जाकर नरेन्द्र मोदी अपने देशी-विदेशी थैलीशाह आकाओं की पूरी सेवा कर पाएंगे, जिनके वो चौकीदार हैं।

का अहम योगदान रहा है। इसलिए इसे हर कहीं आजमाया जायेगा।

जहां तक उन मुद्दों और नारों का सवाल है, जिनसे हवा बना कर नरेन्द्र मोदी सत्ता में आए, वो हवा हो गए। महंगाई पर नियंत्रण नहीं हो सका। काला धन नहीं आया। और भी जो वादे किए थे, उन्हें पूरा करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया और न उठाएंगे। बस हर जगह निजीकरण की पूरी तैयारी है। रेलवे से लेकर कोयला खदान और रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भी सरकार ने विदेशी पूंजी को खुलकर खेलने की पूरी छूट दे दी है। ये छूट अभी और दी जाएगी, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था की हालत खराब है। नरेन्द्र मोदी का 'मेक इन इंडिया' लगता है, फेल ही हो जाएगा। विदेशी निवेश तो कुछ हुआ नहीं। फ़िर जूठन चाटने को कैसे मिलेगी। इसलिए जनता को अभी तमाशा दिखाने पर जोर है। तरह-तरह के तमाशे हैं सबसे जोरदार है। सफ़ाई अभियान। इस अभियान पर आम लोग भी हंस रहे हैं और सरकार की खिल्ली उड़ रही है, पर मोदी को इससे क्या। नीति आयोग में स्मृति ईरानी की जगह सुरक्षित हो गई। काश नीता अंबानी को भी ले आते तो नीतियां जहरदस्त बनतीं। बहरहाल, मोदी की आलोचना करते हुए उन्हें ही सारा दोष देना उचित नहीं होगा। जो लोग भ्रम में थे, वो निराश हो सकते हैं, पर ये तो पहले से ही साफ़ था कि ये शख्स सत्ता में आने पर क्या करेगा। और जो इससे उम्मीद थी, वह बखूबी कर रहा है।

अब सवाल ये है कि क्या नरेन्द्र मोदी का कोई विकल्प है और है तो वह विकल्प कब तक सामने आ सकेगा। फ़िलहाल, सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा लगता है कि नरेन्द्र मोदी का निकट भविष्य में कोई विकल्प नहीं है। छल-छद्म की राजनीति अभी और परवान चढ़ेगी। भारतीय राजनीति में घोर अंधकार का युग तो अभी शुरू ही हुआ है। ये लंबा चलेगा। ग़रीब किसानों-मज़दूरों और निम्न मध्यम वर्ग को अभी घोर दुख झेलने हैं। नरेन्द्र मोदी की सरकार यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सरकार जनता को मिली मामूली सुविधाएं भी छीनकर उसका स्वत्वहरण करेगी। उनके साथ देश-विदेश के तमाम थैलीशाह गोलबंद हैं।

भूलना नहीं होगा कि विकल्पहीनता के शून्य की वजह से ही नरेन्द्र मोदी सत्ता में आ सके। अब बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि ये अलग बात है कि कांग्रेस सरकासर भ्रष्ट थी, पर इस सरकार के मुकाबले ठीक थी। जनविकल्प के अभाव में इस सोच को ग़लत नहीं ठहराया जा सकता। दरअसल, यही तो इस नकली जनतंत्र का असली भ्रम है। हर पांच साल के बाद जनता ये समझती है कि ये ग़लत है, तो दूसरा सही होगा। और फ़िर से जाल में फंस जाती है। अगर जनविकल्प हो तो जनता ये समझ सकेगी कि दरअसल, कांग्रेस, भाजपा, जदयू सपा, तृणमूल और वामपंथी दलों में कोई मूलभूत अंतर नहीं है। सभी एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं। सभी लूटेरे हैं। कोई नागनाथ है तो कोई सांपनाथ। वोट की राजनीति एक छलावा बनकर रह गई है। जनता को यह बात समझाने वाले वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में दूर-दूर तक नज़र नहीं आते। ऐसे में, जनता को पीड़ा के एक लम्बे दौर से गुजरना होगा। वंचना बढ़ेगी। दरिद्रता का रोद्र रूप सामने आएगा। बेकारी, वेश्यावृति, आत्महत्याएं, बलात्कार, दंगे। यही वो चीज़ें हैं जो वर्तमान सरकार जनता को दे सकती है और दे रही है। इसके सिवा सकारात्मक कुछ भी नहीं।

महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड आरै जम्मू-कश्मीर की सत्ता पर काबिज़ होने के बाद संघ की नज़र उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की सत्ता पर है, जहां उसे सफलता मिलना तय है। इसकी वजह है वहां की नाकारा और भ्रष्ट सरकारें। जिस जनता परिवार के दलों के महाविलय की योजना बनाई जा रही है, वह कभी नरेन्द्र मोदी की सत्ता को चुनौती नहीं दे पाएगी। लालू-मूलायम-नीतीश-ममता चाहे बातें जितनी बड़ी-बड़ी कर लें, चुनाव के मैदान में मोदी का सामना नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह है इनकी अंतर्निहित कमजोरी। मोदी के भय से ये एकजुट तो हो रहे हैं, पर अपने शासन में इन्होंने क्या किया है, जनता इसका हिसाब तो मांगेगी ही। इनके गठबंधन का आधार ही है मोदी के भारत-विजय अभियान को रोकना। पर पहले ये ख़तरा इनकी समझ में नहीं आया था। जब लगा कि सत्ता हाथ से चली जाएगी तो आपद धर्म के तहत एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें भी पूरी सफ़लता नहीं मिल रही।

वामपंथियों के शासन से त्रस्त होकर जनता ने ममता बनर्जी को सत्ता सौंपी। बदले में मिला क्या? ममता बनर्जी के कतिपय सांसद भ्रष्टाचार और घोटाले में संलिप्त हैं। ममता बनर्जी के चीखने-चिल्लाने से बात बनने वाली नहीं। अमितशाह ने वहां बिसात बिछा दी है। यही हाल बिहार का है। नीतीश की सरकार ने कुछ खास नहीं किया। अपराधियों पर रहमोंकरम जरूर रहा। यूपी में तो सपा प्रमुख मुलायम अपना समय नाच देखने में व्यतीत कर रहे हैं। कुनबापरस्ती का जैसा उदाहरण उन्होंने पेश किया है, वैसा कहीं और नहीं दिखाई पड़ता। प्रदेश में अखिलेश सरकार हर मोर्चे पर विफल है। थाने में सिपाही बालिकाओं का अपहरण कर उनके साथ दुष्कर्म कर रहे हैं। जाहिर है ऐसी सरकार पर जनता का भरोसा क्यों रहेगा। अगर संघ ने यूपी में दंगे प्रायोजित किए तो सरकार उन्हें रोक क्यों नहीं सकी। अल्पसंख्यकों के सबसे बड़े ख़ैरख़्वाह होने का दम भरने वाले मुलायम प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। ये मुंगेरीलाल के हसीन सपने से ज़रा भी कम नहीं। चुनाव होते ही उन्हें अपनी औकात पता चल जाएगी। विवाह समारोहों वाले गठबंधन भला कितने कारगर होंगे?

मायावती जैसी दलित नेत्रियों का ज़माना भी लद चुका है। जनता मूक भले ही हो, पर वो कुछ समझती नहीं, ऐसा नहीं है। ग़रीबों के नाम पर राजनीति कब तक चलेगी और वह भी हीरो का हार पहनकर। अल्पसंख्यकवाद की राजनीति करने वालों के दिन लदे। अब देश में हिंदूवाद की राजनीति के उभार का दौर है। यह अभी शुरू ही हुआ है पूरे जोर-शोर से तो जल्दी खत्म नहीं होगा। कांग्रेस ने सपने देखने तक बंद कर दिए। ये उसने सही किया है। कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं है। रहा सवाल वामपंथियों का, तो जिस दिन उन्होंने मनमोहन सरकार से समर्थन वापस लिया था, उसी वक्त से वो राजनीति के ऐसे बियाबान में चले गए कि अब मुख्यधारा में आ नहीं सकते। नरेन्द्र मोदी की सत्ता के लिए ये कहीं से चुनौती नहीं हैं। तो फ़िर? क्या नरेन्द्र मोदी और संघ की सत्ता देश में और भी मजबूत होगी? इसकी जड़ें और भी गहरी होंगी? लगता तो ऐसा ही है। ये प्रतिक्रियावाद का दौर है। ये अंधकार का दौर है। ये वो दौर है जब जनता को और भी दमन-उत्पीड़न-अन्याय सहने के लिए तैयार रहना है। दस प्रतिशत को सब कुछ मिलेगा, 90 प्रतिशत जनता से छीनकर।

जनकवि नागार्जुन ने लिखा था-

धनपिशाच की चक्रचेतना घूम रही है
शासन की गति किस पिनक में झूम रही है
क्रियाहीन चिंतन का कैसा अनाचार है
दस प्रतिशत आलोक और बस अंधकार है।

तुर्की-ब-तुर्की

''....स्वयं को अराजक कहने वाले (केजरीवाल) को जंगलों में जाकर नक्सलियों में शामिल हो जाना चाहिये''

(दिल्ली के रामलीला मैदान में चुनावी रैली को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भाजपा के पसीने छुड़ाने वाले अरविंद केजरीवाल के लिए उक्त शब्द कहे।)

हमारा कहना है:-

- केजरीवाल को मोदी जी आपने 'सही' सलाह दी है। दिल्ली के चुनावी समुद्र में भाजपा के डूबते जहाज को बचाने का एकमात्र यही तरीका रह गया है। केजरीवाल के पीछे लामबंद होती दिल्ली की जनता को तो आप बरगला नहीं पा रहे हैं। लिहाज़ा, आपका स्वाभाविक ध्यान इस पर ही केन्द्रीत है कि केजरीवाल को ही मैदान से लुप्त कर दिया जाय।
- लगता है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आर एस एस) और विश्व हिन्दू परिषद जैसे सहयोगी संगठनों द्वारा वोटरों की साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण की तिकड़में दिल्ली में वांछित रंग नहीं दिखा पा रही हैं। यह भी लगता है कि आपके कार्पोरेट यारों द्वारा खोली गयी थैलियों से भी दिल्ली के वोटरों को खरीदने का मनसूबा पूरी तरह सिरे नहीं चढ़ पा रहा है। ऐसे में आपके नारेबाज़ शासन की खुलती पोल एक प्रश्न चिन्ह की तरह खड़ी हो रही है। कहीं दिल्ली का चुनाव हार गये तो इससे आपकी अपनी उल्टी गिनती न शुरू हो जाये।
- दरअसल दिल्ली चुनाव में मुकाबला 'सुशासन' के दो मॉडलों के बीच है। एक मॉडल भाजपा का है, जिसमें नारे तो लोकलुभावन होते हैं पर लक्ष्य कार्पोरेट जगत के मुनाफ़े को येन-केन प्रकारेण आसमान तक ले जाने का रहता है। दूसरा मॉडल 'आप' पार्टी का है जो जनता को वास्तविक राहत देने के कदम उठाती है और इस प्रयास में भ्रष्टाचार, मंहगाई, दलाली, कार्पोरेट लूट से जमकर मुकाबला चलता है। अपने अनुभव व संगठन के बल पर भाजपा के मॉडल को मोदी जी आप बखूबी सिरे चढा रहे हैं। आपका असली डर यह है कि कहीं अपनी पुरानी 'भूलों' से सबक लेकर 'आप' पार्टी भी अपने मॉडल को सिरे न चढा दे। क्योंकि यदि दिल्ली में ऐसा हो गया तो सारे देश में जनता भाजपाई शासन को एक-एक कर उखाड़ फ़ेंकेगी। मोदी जी स्वयं आपका नम्बर आते भी देर नहीं लगेगी।
- बनवास की जो सलाह मोदी जी आपने केजरीवाल को दी है, वह किसी अन्य अपने विपक्षी दल या नेता को क्यों नहीं दी? ऐसा इसलिए क्योंकि ये तमाम दल व नेता भी उसी मॉडल में यकीन करते हैं जो भाजपा का है। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि मोदी के शासन में कार्पोरेट लूट की फ़ाइलें तेज़ी से निकल रही हैं। इसी लिए जनता भी विकल्पहीनता की स्थिति में भाजपा को मजबूरी में वोट देती आई है। 'आप' पार्टी के दिल्ली मैदान में होने से जनता को विकल्प का एक सिरा पकड़ने का मौका मिलने जा रहा है। यानी मोदी की चिन्ता केजरीवाल का अराजक होना नहीं, विकल्प होना है।